

## उत्तराखण्ड बजट 2025-26

### चर्चा में क्यों?

उत्तराखण्ड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये **1,01,175.33 करोड़ रुपए का बजट** पेश किया है, जिसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए **बुनियादी ढाँचे** को मज़बूत करना है।

### मुख्य बट्टि

- **बजट प्रस्तुत और वज़िन:**
  - राज्य वित्त मंत्री ने देहरादून स्थित **राज्य विधानसभा** में 1,01,175.33 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।
  - बजट में राज्य के आर्थिक और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये **एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।**
- **क्षेत्रीय फोकस क्षेत्र:**
  - सरकार ने **कृषि, उद्योग, ऊर्जा, बुनियादी ढाँचा, कनेक्टिविटी, पर्यटन और आयुष को प्राथमिकता दी है।**
  - विकास को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे और ग्रामीण विकास पर अतिरिक्त जोर दिया गया है।
- **राजस्व एवं प्राप्तियाँ अवलोकन:**
  - बजट में कुल प्राप्तियाँ 1,01,034.75 करोड़ रुपए अनुमानित हैं, जिनमें शामिल हैं:
    - **राजस्व प्राप्तियाँ** : 62,540.54 करोड़ रुपए
    - **पूंजीगत प्राप्तियाँ** : 38,494.21 करोड़ रुपए
  - **कर राजस्व का योगदान** 39,917.74 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि गैर-कर राजस्व का योगदान 22,622.80 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
- **समावेशी विकास के लिये 'ज्ञान' मॉडल:**
  - यह बजट 'ज्ञान' मॉडल पर आधारित है, जिसमें नमिनलखिति पर ध्यान केंद्रित किया गया है:
    - गरीब (Poor)
    - युवा
    - अन्नदाता (Farmers)
    - नारी (woman)
- **उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा:**
  - औद्योगिक विकास और उद्यमता को समर्थन देने के लिये बजट में नमिनलखिति शामिल हैं:
    - **एमएसएमई उद्योगों** के लिये 50 करोड़ रुपए।
    - मेगा उद्योग नीति के लिये 35 करोड़ रुपए।
    - स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिये 30 करोड़ रुपए।
    - आर्थिक वसितार को बढ़ावा देने के लिये **मेगा परियोजना योजना** के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए।
- **क्षेत्रवार प्रमुख आवंटन:**
- **जल संसाधन और सचिाई:**
  - **जमरानी बाँध, साँग बाँध, लखवाड़ परियोजना** के लिये धन आवंटित किया गया है।
  - राज्यों के लिये विशेष पूंजी सहायता के अंतर्गत 1,500 करोड़ रुपए।
  - **जल जीवन मशिन** के लिये 1,843 करोड़ रुपए।
  - शहरी जलापूर्ति सुधार के लिये 100 करोड़ रुपए।
- **सड़क, परविहन और बुनियादी ढाँचा:**
  - 220 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी।
  - 1,000 कमी सड़कों का पुनर्निर्माण तथा 1,550 कमी सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा।
  - **सड़क सुरक्षा पहल** के लिये 1,200 करोड़ रुपए।
  - 37 नए पुल बनाए जायेंगे।
  - **PMGSY योजना** के अंतर्गत 1,065 करोड़ रुपए आवंटित।
  - **नागरिक उड्डयन विभाग** के लिये 36.88 करोड़ रुपए।
- **पर्यटन और सांस्कृतिक विकास:**

- टहिरि झील वकिस के लयि 100 करोड रुपए ।
- मानसखण्ड योजना के लयि 25 करोड रुपए ।
- वाइबरेट वलैज योजना के लयि 20 करोड रुपए ।
- नये पर्यटन स्थलों के लयि 10 करोड रुपए ।
- चारधाम सडक नेटवर्क सुधार के लयि 10 करोड रुपए ।
- पर्यावरण और सतत वकिस:
  - कैम्पा योजना के लयि 395 करोड रुपए आवंटति ।
  - जलवायु परविरतन शमन के लयि 60 करोड रुपए ।
  - स्परगि एवं रविर रजिवेनेशन अथॉरटी के लयि 125 करोड रुपए ।
  - सार्वजनकि वनरोपण परयोजनाओं के लयि 10 करोड रुपए ।
- सामाजकि सुरक्षा और कल्याण:
  - सामाजकि सुरक्षा योजनाओं के लयि 1,811.66 करोड रुपए आवंटति ।
  - वभिनिन कल्याणकारी सब्सडी के लयि 918.92 करोड रुपए अलग रखे गए ।
  - खाद्य सुरक्षा योजना के लयि 600 करोड रुपए ।
  - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लयि 207.18 करोड रुपए ।
  - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लयि 54.12 करोड रुपए ।
  - EWS आवास अनुदान के लयि 25 करोड रुपए ।
  - नमिन आय वाले परिवारों के लयि रसोई गैस सब्सडी हेतु 55 करोड रुपए ।
  - पर्यावरण मतिर बीमा योजना के लयि 2 करोड रुपए ।
  - राज्य परविहन बसों में मुफ्त यात्रा उपलब्ध कराने के लयि 40 करोड रुपए ।
  - राज्य खाद्यान्न योजना के लयि 10 करोड रुपए ।
  - अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को नमक पर सब्सडी देने के लयि 34.36 करोड रुपए ।
- वकिस पर रणनीतिक ध्यान:
  - यह बजट समग्र वकिस और सतत वकिस के प्रतियोग्य सरकार की प्रतबिद्धता को दर्शाता है ।
  - बुनियादी ढाँचे, सामाजकि कल्याण, पर्यावरण और आर्थकि वसितार पर ज़ोर देकर सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड नवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है ।

## प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना

- यह एक केन्द्र सरकार की योजना है, जसि वर्ष 2000 में असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सडक संपर्क प्रदान करने के लयि शुरू कयि गया था ।
  - यह योजना मूलतः 100% केन्द्र प्रायोजति पहल थी, लेकिन वतितीय वर्ष 2015-16 से इसका वतितपोषण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा कयि जाने लगा ।
  - इस योजना के वभिनिन चरणों के अंतरगत लगभग 800,000 किलोमीटर ग्रामीण सडकें बनाई गई हैं और 180,000 बस्तियों को जोड़ा गया है ।

## जीवंत गाँव कार्यक्रम

- यह एक केंद्र प्रायोजति योजना है, जसिकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 (2025-26 तक) में उत्तरी सीमा पर स्थति गाँवों के वकिस के लयि की गई है, जसिसे चनिहति सीमावर्ती गाँवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा ।
- यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सकिमि और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करेगा ।
- इसमें 2,963 गाँव शामिल होंगे, जनिमें से 663 को पहले चरण में शामिल कयि जाएगा ।
- ज़िला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायतों की सहायता से जीवंत ग्राम कार्य योजनाएँ बनाई जाएंगी ।
- सीमा क्षेत्र वकिस कार्यक्रम के साथ कोई सामंजस्य नहीं होगा ।